Production on malaria vaccines

2190. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the status of production of malaria vaccines, both overseas and in this country; and

(b) since when these have been under development and the status of the research and development effort in this regard, at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) Malaria vaccines are not produced in India and no report of commercial production of malaria vaccines in other countries has been brought to the attention of the Government.

(b) Based on R&D efforts initiated in the Seventies, malaria vaccines have been developed and experimental trials have been conducted by the scientists in U.S.A.

Foreign currency deposits by NRIs

2191. SHRI RAOOF VALIULLAH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the total foreign currency deposits by Non Resident Indians outstanding by the Commercial Banks and the debt servicing obligations on these deposits yearwise since the inception of the scheme;

(b) whether interest rate offered by Government is higher than London Inter Bank Offered Rate (LIBOR) and whether Government are aware that it is a costly way of raising foreign exchange; and

(c) whether Government are also aware that foreign exchange reserves in the country are utilised for creating, rupee-backed assets and if so whether Government propose to review the FCNRI term deposit scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Recommendation of Planning Commission

2192. SHRI RAOOF VALIULLAH: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) what are the details of major steps that have been recommended by the Planning Commission to improve the resource position of the Government;

(b) whether Planning Commission has also drawn the attention of the Government to the fact that the entire plan expenditure of the Centre is financed out of borrowed funds and if so, the remedial measures intended to be taken by the Government; and

(c) whether, in view of this, Government are contemplating a change in the terms of reference of the 9th Finance Commission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SUKH RAM): (a) As a part of its normal functions, the Planning Commission undertakes reviews of resource position in consultation with the Ministry of Finance. For improving the resources position, the Government is conscious of the need for raising the budgetary savings, improving the financial performance of the public-sector undertakings and for containing the growth in non-plan expenditure.

(b) The Seventh Plan has pointed out that due to depletion of budgetary savings and the inability of the public sector enterprises to generate adequate internal resources, there is an increasing reliance on borrowings for financing public sector outlay. Hence the Government is seized of the need for improving public savings. Besides, while presenting the 1987-88 budget, the Prime Minister has stated that the budgetary deficit estimated at Rs. 5688 crores for the current year which also reflects Government's borrowings, shall not be allowed to be exceeded.

(c) The Government has already announced the Constitution of the 9th Fiance Commission. There is no proposal at present to change the terms of reference.

अन्तरिक्ष में दूसरे भारतीय व्यक्ति का भेजा जाना

2193. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिक्ष में दूसरा भारतीय व्यक्ति भेजे जाने की वर्तमान प्रगति क्या है ; और

(ख) भारत द्वारा अगले दस वर्षों के दौरान अन्तरिक्ष अनुसंधान के कौन-कौन से कार्यक्रम हैं जो आरम्भ किए जाने को संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन):

(क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) आगामी दस वर्षीय अवधि में 1987-90 की अवधि, 1980 90 दशाब्द के लिए अन्तरिक्ष प्रोफाइल में अन्तर्निहित है तथा 1997 तक की अवधि अगले दशाब्द 1990-2000 के लिए अन्तरिक्ष प्रोफाइल में अन्तर्निहित है ।

आगामी दशाब्द 1990-2000 के लिए अन्तरिक्ष प्रोफाइल के लिए कार्यक्रम अध्ययन अन्तिम रूप की प्रक्रिया में हैं । 1980-90 दशाब्द के प्रोफाइल में शामिल विविध परियोजनाएं/कार्यक्रम, जो कि उपलब्धि के विविध चरणों के अन्तर्गत हैं, का ब्यौरा निम्न प्रकार है :--

प्रथम प्रचालनात्मक सुदूर संवेदन उपग्रह, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई०आर०एस०) का डिजाइन, संविरचन और प्रमोचन तथा इन्सैट-1 बी के परवर्ती संचार उपग्रह इन्सैट-I सी एवं I डी, जिनका डिजाइन भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन जिन्हें विदेश से प्राप्त और प्रमोचित किया जा रहा है ।

– इन्सैट की द्वितीय पीढ़ी के उपग्रहों (इन्सैट-II) का विकास ।

– संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस०एल०वी०) और सबट्रोपिक उपग्रहों का विकास तथा 1000 कि०ग्रा० भार की श्रेणी के आई०आर०एस० उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (पी० स० ल०वी०) का विकास ।

– द्वितीय पीढ़ी के इन्सैट उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम भू-तुल्यकालिक प्रमोचक राकेटों के विकास के लिए जरूरी निम्नतापी का विकासप्रारम्भ करना ।

इंडियन टोबेको कम्पनी द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

2194. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन टोबेको कम्पनी पर 1300 करोड़ रुपए के उत्पाद शुल्क के अपवंचन का आरोप है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) : (क) मैसर्स इंडियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड के नाम सिगरेटों और पीने वाले तम्बाकू विभागों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन के आरोप से सम्बन्धित 30 कारण बताओ नोटिस न्यायनिर्णय के लिए विचाराधीन पड़े हैं । इन कारण बताओ नोटिसों में लगभग 920 करोड़ रुपयों की राशि अन्तर्गस्त है ।

(ख) बताई गयी उपयुक्त धनराशि की वसूली का प्रश्न कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के पश्चात ही उठेगा । इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।